बिहार की अर्थव्यवस्था : अवसर एवं चुनौतियाँ

डॉ॰ अभिषेक आनन्द
सहायक व्याख्याता
टी॰एन॰बी॰ कॉलेज, भागलपुर

सार: बिहार देष का जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी 79% जनता का मुख्य रोजगार कृषि है। कृषि क्षेत्र में बिहार का विकास दर औसतन देष की दर से बेहतर है। अगर फिर से देष की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अब भी कम है। औद्योगीकरण में बिहार काफी सफल नहीं रहा है। बिहार सरकार के लिए आवष्यक है कि षिक्षा तथा रोजगार में वह नए अवसर प्रदान करें और संसाधन उपलब्ध कराए। षिक्षा संस्थानों में सुधार तथा औद्योगीकरण से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा बिहार जो पलायन की समस्या से ग्रसित है उसमें निष्चित रूप से काफी कमी आएगी। बिहार में संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो राज्य में अवसर के काफी साधन उपलब्ध है।

परिचय :

बिहार देष में ऐतिहासिक एवं राजनैतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार बौद्ध धर्म एवं अपनी प्राचीन षिक्षा पद्धति जैसे नालंदा विष्वविद्यालय एवं विक्रमषिला विष्वविद्यालय के लिए पूरे विष्व में जाना जाता था, वहीं दूसरी ओर बिहार ने देष को प्रथम राष्ट्रपति भी दिया। बिहार आज जहाँ एक ओर सबसे ज्यादा आई॰ए॰एस॰ एवं अन्य परीक्षाओं में सबसे अधिक मात्रा में छात्र उत्तीर्ण तथा अपना योगदान देते हैं वहीं दूसरी ओर बिहार BIMARU राज्यों की श्रेणी में पिछड़ेपन, गरीबी, जातिवाद, संसाधनों की कमी तथा अन्य समस्याओं से जूझ रहा है। बिहार के विकास में कई चुनौतियाँ विद्यमान है जिस कारण से राज्य में औद्योगिकरण, रोजगार, स्वास्थ्य तथा षिक्षा व्यवस्था काफी उपेक्षित है। राजनैतिक रूप से जागरूक होने के बावजूद भी राज्य मूलभूत समस्याओं से ग्रसित है। बिहार राज्य के लिए प्राथमिक समस्या असाक्षरता, बेरोजगारी, रोजगार के अवसरों में कमी, षिक्षा व्यवस्था में कमी इत्यादि है। जिस कारण राज्य में पलायन की समस्या है और लोग षिक्षा तथा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर जाने पर विवष हैं।

ऐसा नहीं है कि बिहार में अवसरों की कमी है। मगर उसके लिए सरकार को सामाजिक ऊपरीपूंजी पर निवेष करना, उत्पादकों के लिए संसाधन मुहैया कराना तथा षिक्षा में गुणवत्तापूर्ण संसाधनों, षिक्षकों तथा संसाधनों को प्रदान करना है। राज्य में रोजगार के कम अवसर होने के कारण षिक्षित लोग पलायन कर जाते हैं और उनका योगदान जो अपने प्रदेष तथा समाज में होना चाहिए वह नहीं हो पाता। इसलिए बिहार जो अब प्रगति के राह पर है उसे अपने औद्योगिक नीतियों तथा षिक्षा नीतियों की ओर सुदृढ़ बनाने की आवष्यकता है।

लेख का उद्देष्य

इस लेख का लक्ष्य उन कारणों को जानना है जो बिहार जैसे राज्य, जिसकी इतनी सुनहरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। कैसे आज भारत देष के पिछड़े राज्यों में गिना जाने लगा है। वे कौन से कारण है जो बिहार के तरक्की एवं विकास में बाधक है तथा वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें विकास के अवसर विद्यमान है। इस लेख से बिहार सरकार को उचित नीति को बनाने में मदद मिलेगी जिससे वे उन प्राथमिक क्षेत्रों में ध्यान दे सकें जिनमें विकास की ज्यादा संभावनाऐं है और बिहार जो तरक्की की राह पर चल पड़ा है उसे और प्रभावपूर्ण बनाया जा सकेगा।

बिहार में विकास की चुनौतियाँ

बिहार के विकास में कई चुनौतियाँ है जो निम्नलिखित हैं :–

1. कृषि क्षेत्र :

कृषि बिहार के लोगों का मुख्य रोजगार एवं आय का श्रोत है। इसका कारण यह है कि 79% बिहार की जनसंख्या कृषि पर आश्रित है और ज्यादातर लोग गाँवों में रहते है। Bihar Economic Survey, 2018-19 के अनुसार 2001 से 2011 में भारत में शहरीकरा 27.8% से 31.2% पहुँच गया है जो कि 3.4% की बढ़ोतरी है, वही दूसरी ओर बिहार में शहरीकरण 10.5% से 11.3% (2001–2011) हुई है जो कि 0.8% की बढ़ोतरी है। बिहार में

39.1 हजार गाँव प्रषासन के लिए एक चुनौती है क्योंकि आज भी गाँव निम्न मूलभूत समस्याओं से ग्रसित है, जैसे–बिजली, शौचालय साधन, सड़क, विद्यालय इत्यादि।

बिहार का क्षेत्रफल में भारत का 8.6% हिस्सा है मगर कृषि योग्य जमीन बिहार के पास केवल 3.8% ही है। Agricultural Road Map 2017-2022 के अनुसार 91% सीमान्त किसान है जिनके पास खेती के लिए काफी कम जमीन है, जो कम आय का मुख्य कारण है।

Area of Operational Holding (Size) Bihar

S.No.	Size (Hectares)	Total Holdings				
		Nos(000s)	%	Area (Hectar)	%	Avg. Area per holding
1	Marginal	14744	91.06	3669	57.44	0.2
2	Small	948	5.86	1186	18.57	1.25
3	Semi-Medium	415	2.56	1073	16.50	2.59
4	Medium	81	0.5	415	6.5	5.12
5	Large	16191	0.02	45	0.7	15.00

Source : Agriculture census, 2010-11, Govt. of India.

ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में कितनी असमानता है। 91% किसानों के पास जहाँ औसतन केवल 0.2 हेक्टेयर जमीन है, वहीं 0.026 किसानों के पास औसतन 15 हेक्टेयर जमीन है। यह कृषि क्षेत्र तथा किसानों के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है।

अगर बिहार की प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्ति देखी जाए तो वह देष के औसत से कम है तथा इसमें उत्पादन बढ़ाने के अवसर व्याप्त है। बिहार में निम्न साक्षरता के कारण किसानों को तकनीकि बीजों तथा नए उपकरणों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है तथा वे नए उपकरणों को उपयोग करने से हिचकते है। जिस कारण राज्य जैसे–हरियाणा, पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्ति बिहार के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, और कृषि क्षेत्र में भी उनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाती है। परंतु बिहार के किसान उतनी मात्रा में उत्पादन प्राप्ति नहीं कर पाते और प्रति व्यक्ति आय में पीछे छुट जाते है।

वर्ष	क्षेत्र (000 हेक्टेयर)	प्रति हेक्टेयर प्राप्ति (किग्रा॰)	क्षेत्र (000 हेक्टेयर)	प्रति हेक्टेयर प्राप्ति (किग्रा॰)
Rice				
2010–11	2845	1094	42863	2240
2011–12	3351	2458	44006	2393
2012–13	3299	2523	42754	2461
2013–14	3151	2110	43949	2424
Wheat				
2010–11	2100	2426	29069	2990
2011–12	2142	3049	29865	3117
2012–13	2208	2797	30003	3117
2013–14	2149	2855	31188	3075
Barley				
2010–11	12	1327	705	2360
2011–12	11	1542	643	2516
2012–13	10	1460	695	2521
2013–14	10	1398	674	2686

Source : Directorate of Economics & Statistics, Bihar.

बिहार के GDP में कृषि का योगदान 18% है और कृषि का विकास दर 4.6% है जो कि भारत के 3.6% की कृषि वृद्धि दर से अधिक है। परंतु लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है और सरकार को इस क्षेत्र में वृद्धि दर को और बढ़ाना होगा तथा किसान जो कृषि पर आधारित हैं उनकों नए तकनीक तथा शहरों में अवसर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना होगा।

2. षिक्षा व्यवस्था :

भारत में षिक्षा के अधिकार के कानून होने के बावजूद भी बिहार अभी भी साक्षरता के मापदंड पर अन्य कई राज्यों से पिछड़ा हुआ है। केरल में जहाँ 100% साक्षरता है वही बिहार में साक्षरता तथा षिक्षा व्यवस्था में सुधार एक चुनौती है जिसका सीधा प्रभाव बिहार के विकास पर पड़ता हे। इसका मूल कारण बेरोजगारी तथा षिक्षा के प्रति लोगों में प्रेरणा की कमी है।

Year	2011	2001
Literacy	61.80%	47.00%
Male Literacy	71.20%	59.68%
Female Literacy	51.50%	33.12%

Source : Bihar Economic Survey, 2018-2019.

बिहार में साक्षरता के साथ–साथ षिक्षा व्यवस्था में भी व्यापक सुधार की आवष्यकता है। बिहार में केवल जनसंख्या का मात्र 1% ही उच्च षिक्षा में दाखिला लेता है जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। Futab के अध्यक्ष के अनुसार, ''राज्य में छात्रों की संख्या के अनुसार अच्छे संस्थानों की काफी कमी है जैसे–इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज तथा अन्य व्यवसायिक पढ़ाई। इसी के कारण यहाँ के प्रतिभावान छात्र अन्य राज्य के संस्थानों में अच्छी षिक्षा प्राप्त करने चले जाते है।'' अगर हम राज्य के षिक्षा संस्थानों को देखे तो यहाँ षिक्षकों की काफी कमी है जिस कारण कई विषयों में छात्र दाखिला तो लेते हैं मगर षिक्षक नहीं होने के कारण वे कक्षा में नहीं जा पाते और उनका उचित ज्ञानवर्धन नहीं हो पाता। इस कारण बिहार के लोग अच्छी षिक्षा की तलाष में अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हे।

सरकार को चाहिए कि राज्य के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण षिक्षा प्रदान करे जिससे आने वाले भविष्य में जिम्मेदारी से कार्य करें तथा राज्य से षिक्षा के लिए पलायन रूक सके।

3. रोजगार :

बिहार से लोगों का पलायन चाहे वह षिक्षा के लिए हो या रोजगार के लिए हमेषा से एक राजनैतिक बहस रहा है। सरकार को चाहिए कि वह राज्य के युवाओं तथा बुद्धिजीवियों के पलायन को रोकें। रोजगार के लिए निवेष करें तथा उचित संसाधन उपलब्ध कराए। बिहार अन्य राज्यों की अपेक्षा राज्य में निवेष तथा उद्योगों को आकर्षित करने में विफल रहा है। इसका मुख्य कारण संसाधनों की कमी है। विकास एवं संवृद्धि अर्थषास्त्री हर्षमैन के अनुसार, "SOC encourage private investment" अर्थात् अगर सामाजिक ऊपरीपूंजी अगर अर्थव्यवस्था में व्याप्त हो तो वह खुद ही उद्योगों तथा निवेषों को आकर्षित करती है जो राज्य या अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करती है।

बिहार से लोगों के पलायन का मुख्य कारण यहाँ रोजगार तथा अवसरों की कमी है और रोजगार की कमी यहाँ पर उद्योगों का न होना है। बिहार में आधारभूत संसाधनों की कमी को दूर करना तथा उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उचित एवं आकर्षक नीति की आवष्यकता है। राज्य सरकार को उद्योगपतियों को भरोसा दिलाना होगा तथा Red Tapism को खत्म करना होगा जिससे सरलता से अपने उद्योग यहाँ शुरू कर सकें और बिहार में रोजगार के अवसर पैदा हो सकें।

इसी आलोक में बिहार सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को लाया है :–

Bihar Industrial Investment Policy, 2016

इसका लक्ष्य प्रतिवर्ष 15% की विकास दर को प्राप्त करता है। रोजगार के अवसर को बढ़ावा तथा सभी क्षेत्रों में 5 लाख रोजगार पैदा करना। 15000 करोड़ का निवेष प्राप्त करना, लोगों में असमानता को दूर करता तथा उन लोगों को मुख्य धारा में लाना और रोजगार प्रदान करना जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं।

इसके लिए राज्य सरकार ने कौषल विकास योजना प्रारंभ किया है जो युवाओं में तकनीकि साक्षरता प्रदान कर उन्हें किसी भी उद्योग में काम करने योग्य कुषल बनाना है। कुषल मजदूर आज के उद्योगों की मांग है और जब उद्योगों को कहीं प्रचुर मात्रा एवं सस्ते में मजदूर मिलता है तो वह उनके लिए आकर्षण का कारण होता है।

4. बिहार की अर्थव्यवस्था :

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः रोजगार के लिए कृषि पर आधारित है, वहीं GDP में तृतीय श्रेणी के उद्योग का सबसे अधिक योगदान है।

त्वरित अनुमान के अनुसार वर्तमान मूल्य पर 2017–18 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 4,87,628 करोड़ रु॰ था जो वर्ष 2011–12 के स्थिर मूल्य पर यह आँकड़ा 3,61,504 करोड़ रु॰ है।

वर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
बिहार	21750	22201	22776	23223	23987	25950	28485
बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में	34.3	33.9	33.2	31.9	30.8	31.6	32.9

Source : Bihar Economic Survey, 2018-2019.

वर्ष 2017–18 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का 32.9% था जों पिछले 2 वर्षों की अपेक्षा सुधार को दर्षाती है।

स्थिर मूल्य (2011–12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

क्षेत्र	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
प्राथमिक	25.8	27.1	23.4	22.2	21.9	21.8	20.2
द्वितीय	18.8	15.6	19.3	20.9	19.7	18.6	17.5
तृतीयक	55.8	57.2	55.3	56.9	58.3	59.6	62.3

स्त्रोत :–अर्थषास्त्र एवं सांख्यिकी निदेषालय, बिहार सरकार

5. गरीबी तथा असमानता

बिहार राज्य देष का तीसरा सबसे बड़ा वाला राज्य है जहाँ बड़ी मात्रा में लोग गरीबी रेख के नीचे जी रहे हैं। बिहार में गरीबी अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है।

गरीबी रेखा के नीचे प्रतिषत, 2012

झारखण्ड – 37
बिहार – 34
उत्तर प्रदेष – 29
तमिलनाडु – 12

Source : World Bank Report, 2012.

लेकिन 2005 के बाद बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा गरीबी दर काफी तेजी से गिर रही है, दोनों ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में। 2005 में ग्रामीण में गरीबी जहाँ 56% था वह 2012 में गिरकर 34% आ गया। वहीं शहरी क्षेत्र में 2005 में गरीबी जहाँ 44% था वह गिरकर 31% तक आ गया।

बिहार में असमानता दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। मगर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की व्याख्या करें तो वहाँ काफी असमानता है जिसके लिए सरकार को सही नीति बनाने की तथा उनके सुरक्षा पर गंभीरता से विचार करना आवष्यक हे।

6. बाढ़ का प्रकोप :

बिहार का उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है तथा हर साल बाढ़ में भारी संख्या में जान–माल की तबाही देखी जाती है। बाढ़ के कारण सड़क, बिजली, घर–मकान, आदि तबाह हो जाते है। बाढ़ के कारण एक ऐसा दृष्य देखने को मिलता है जिसमें चारों ओर खेत के खेत डुब जाते है तथा पानी में मरे हुए मवेषियों की डुबती उतरती लाषों के कारण पानी एवं वातावरण दूषित हो जाते है जिससे लोगों एवं जानवरों में स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तरह–तरह की बिमारियाँ जैसे– हैजा, कोलरा, आदि उत्पन्न हो जाती है। जिससे बिहार के विकास को काफी नुकसान होता है तथा सारे विकास संबंधित नीति विफल हो जाते है। बाढ़ के कारण हर साल नुकसान झेलते है जिससे वे अपने जीवन–स्तर नहीं ला पाते और पिछड़े रह जाते हैं।

सारांष :–

इस लेख के द्वारा हम कह सकते हैं कि बिहार में ऊपरी सामाजिक पूंजी तथा संसाधनों की कमी राज्य के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। अगर सरकार संसाधनों पर खर्च करे और उचित नीति अपनाए तो निजी क्षेत्र में निवेष करने के लिए प्रेरित होंगे तथा रोजगार के अवसर यहाँ के बेरोजगार युवाओं को प्राप्त होंगे। गुणवत्तापूर्ण षिक्षा प्रणाली अपनाने तथा उच्च षिक्षा के अच्छे संस्थानों के खुलने से यहाँ के युवा जो अच्छी षिक्षा के लिए पलायन कर जाते थे उन पर रोक लगेगी। इसके लिए राज्य को काफी पैसे और निवेष की आवष्यकता पड़ेगी।

संदर्भ :–

1. Directorate of Economics & Statistics, Government of Bihar.
2. Agricultural lemus 2010-11, Govt. of India.
3. Bihar Economic Survey, 2018-19
4. Bihar Economic Survey, 2017-18
5. www.stateherald .com
6. http.//m.timesof india.com
7. www.document.worldbank.org
8. Central Statistical Organisation, Govt. of India.
9. M.L.Jhingan, The Economic of Development and Planning, Chapter 29, Pg. 207